22 june Josh cover-15_may cover pages with new right size & style.qxd 7/10/2015 8:13 PM Page 1

जागरण जोश PLUS

₹1 www.jagranjosh.com खुद को तराशने का
22 जुलाई, 2015 | वर्ष-3, अंक-64

COVER STORY
DIGITAL INDIA
बदलेगी तस्वीर...

www.facebook.com/jagranjosh | www.twitter.com/jagranjosh

• SUCCESS मंत्रा : इरा सिंघल

अपनी मानसिक मजबूती से सिविल सेवा परीक्षा-2014 में टॉप रैंक हासिल करने वाली इरा सिंघल की कामयाबी का मंत्र जानें खुद उन्हीं से ...

• MAT की तैयारी

मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी मैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए कैसे बनाएं राइट स्ट्रेटेजी? जानें जोश एक्सपर्ट्स से ...

08-09 cover1_style sheet Josh fin.qxd 7/13/2015 8:36 PM Page 1

DIGITAL INDIA बदलेगी तस्वीर...

डिजिटल इंडिया...पावर टु एम्पॉवर। इस मंत्र के साथ देश के गांवों, शहरों, प्रशासन, बैंक, हॉस्पिटल, बिजनेस सबको डिजिटल मैप पर लाने का बीड़ा उठाया गया है। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया अभियान में टाटा, रिलायंस, वेदांता, माइक्रोसॉफ्ट जैसी देसी-विदेशी कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है। इरादा हर गांव-पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ना और एक बड़ा आइटी वर्कफोर्स तैयार करना है। दावा करीब 18 लाख नई नौकरियां पैदा करने का भी है। क्या इन इरादों को हकीकत में बदला जा सकेगा? इस मामले में क्या है देश की ताकत और चुनौती? एक नजर...

करीब एक लाख करोड़ रुपये के खर्च से चलने वाले 'डिजिटल इंडिया' अभियान (नोडल एजेंसी सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) का मूल मकसद लोगों का जीवन सहज बनाना, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना है, ताकि लोग घर बैठे अपनी फाइल्स का मूवमेंट जान सकें। किसानों को घर बैठे मंडियों के रेट और युवाओं को रोजगार के अवसर की जानकारी मिल सके। देश-विदेश के उद्योग जगत ने इस महत्वाकांक्षी अभियान को समर्थन दिया है। माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, टाटा, आदित्य बिड़ला, एयरटेल, वेदांता, विप्रो जैसी कंपनियों ने प्रोग्राम में शुरुआती दौर में ही करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। रिलायंस जियो ने देश भर में डिजिटल पिलर्स पर करीब ढाई लाख करोड़ रुपये के निवेश करने का ऐलान किया है। इसके अलावा, वह महत्वपूर्ण शहरों में डिजिटल इंडिया स्टार्ट-अप फंड और एंटरप्रेन्योर हब विकसित कर रहा है, ताकि डिजिटल कारोबार शुरू करने वाले युवाओं को प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। माना जा रहा है कि अकेले इससे 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। दूसरी ओर, टाटा ग्रुप के चेयरमैन सायरस मिस्त्री ने इस साल 60,000 आइटी प्रोफेशनल्स नियुक्त करने की घोषणा की है। भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने भी बेहतर आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1,01,800 करोड़ रुपये

बदलेंगे किसानों के दिन

डिजिटाइजेशन से किसानों को कई फायदे होंगे। उन्हें कब मंडी जाना चाहिए, कहां से सस्ता खाद मिलेगा, यह सारी जानकारी किसान ऑनलाइन माध्यम से हासिल कर सकेंगे। पर्याप्त पैसे मिलने से उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। वे नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकेंगे। इससे नई तरह की एम्प्लॉयमेंट जेनरेट होंगी। इस तरह आइटी के जरिए दूसरे सेक्टर्स में भी नौकरियां पैदा होंगी। हां, डिजिटल इंडिया को प्रभावी बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी, जिसको गांव और छोटे शहरों के लोग भी समझ पाएं और इस्तेमाल कर पाएं।

प्रो. प्रणब सेन, चेयरमैन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

08-09 cover1_style sheet Josh fin.qxd 7/13/2015 8:36 PM Page 2

डिजिटल इंडिया के तहत बीएसएनएल के नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क (एनजीएन) के तहत 30 साल पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलने की योजना है।

का निवेश करने की बात कही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वेदांता ग्रुप की स्टरलाइट इंडस्ट्रीज 40,000 करोड़ रुपये के निवेश से एलसीडी निर्माण संयंत्र लगाएगी, जिससे 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने भी एक लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के काम में 99,500 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके अलावा, वह 44,500 करोड़ रुपये का और निवेश करेगी। सरकार का दावा है कि शहरों से लेकर गांवों तक विभिन्न सेवाओं के डिजिटाइजेशन से करीब 18 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। अगर इस योजना पर सही तरीके से अमल हुआ, तो आने वाले सालों में देश की समूची तस्वीर बदल सकती है...

इनोवेशन ऐंड जॉब क्रिएशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इनोवेशन और जॉब क्रिएशन पर जोर दिया है। उन्होंने *मेक इन इंडिया* के साथ-साथ *डिजाइन इन इंडिया* की सोच विकसित करने की बात कही है। देश और दुनिया में छाये भारतीय आइटी प्रोफेशनल्स का आह्वान किया है कि वे ऐसे डिजिटल उत्पादों का निर्माण करें, जो इंडिया के सवा सौ करोड़ लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों। इसके अलावा, भारतीय युवाओं से गूगल जैसे आविष्कार भारत में भी करने की अपील की है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम के तहत सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इनोवेशन, स्टार्ट-अप और एसएमई को प्रमोट करने का फैसला इसी उद्देश्य से लिया गया है। सरकार चाहती है कि छोटे शहरों से लेकर गांवों तक आइटी रिलेटेड रोजगार पैदा हों। अब तक बीपीओ इंडस्ट्री दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु आदि बड़े मेट्रो शहरों तक सीमित थी, लेकिन अब टियर-टू सिटीज पर भी ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के तहत उत्तरपूर्वी राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीओ खोले जाएंगे, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। यह निर्णय बीते सालों में आइटी-आइटीइएस इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों के सृजन को देखते हुए लिया गया है। इंडिया में करीब 31 लाख प्रोफेशनल्स इससे सीधे तौर पर जुड़े हैं, जबकि एक करोड़ अप्रत्यक्ष नौकरियां क्रिएट हुई हैं।

ई-मोबाइल पर फोकस

एनयूईपीए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर **प्रो. आर.गोविंद** कहते हैं, 'डिजिटल इंडिया' के माध्यम से लाखों नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन इसके लिए नेशनल और स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक स्तर पर स्किल डेवलपमेंट का विकेंद्रीकरण करना होगा, तभी

इस योजना का लाभ मिलेगा। इस समय देश में कंप्यूटर से ज्यादा मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में अच्छी बात है कि सरकार डिजिटल इंडिया को घर-घर पहुंचाने के लिए ई-मोबाइल स्कीम पर फोकस कर रही है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अलावा उसके बारे में सही एजुकेशन, रिचर्स को बढ़ावा देना भी डिजिटल इंडिया को सफल बनाने के लिए जरूरी है।

डिजिटल स्किल डेवलपमेंट

डिजिटल इंडिया को सफल बनाने के लिए आइटी वर्कफोर्स भी चाहिए। इसके लिए आने वाले पांच सालों

तहसीलों का हो डिजिटाइजेशन

ग्राम पंचायतों में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की सफलता ब्लॉक और तहसील लेवल पर होने वाले डिजिटाइजेशन पर निर्भर करेगी। जहां तक नौकरियों का सवाल है, तो पंचायतों और तमाम दूसरे सरकारी संस्थानों के नेटवर्क को मैनेज करने के लिए टेक्निकल लोगों की जरूरत होगी। अगर स्किल की बात करें, तो विशेष सेक्टर्स की पहचान कर उसके मुताबिक स्किल डेवलपमेंट करना होगा। लंबे परिप्रेक्ष्य में विजन बनाने की जरूरत होगी, जिससे कि समग्र विकास हो सके। ई-क्रांति के लिए हमारा दिमाग, सोच, प्रशिक्षण सब कुछ डिजिटल होना चाहिए।

ओसामा मंजर, फाउंडर ऐंड डायरेक्टर, डिजिटल एम्पॉवरमेंट फाउंडेशन

डिजिटल इंडिया : बड़ी चुनौतियां

- सबसे बड़ी चुनौती है, डिजिटल लिटरेसी
- नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम की धीमी गति परेशानी का सबब
- इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य ढांचागत समस्याएं भी हैं रुकावट
- ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाना है बड़ा टास्क
- एटीट्यूड यानी लोगों का माइंडसेट बदलना भी एक चुनौती
- गांवों के साथ-साथ शहरों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाना
- इंग्लिश के अलावा कम्युनिकेशन जैसी सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना
- आम लोगों की क्रय शक्ति भी अहम है, जिससे कि वे स्मार्ट फोन खरीद सकें
- हर पंचायत के स्तर पर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्वाइंट बनाना बड़ा चैलेंज है
- इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का उत्पादन सिर्फ शहरों तक सीमित
- गांवों के युवकों को टेक्निकल ट्रेनिंग देना

10-11 cover1_style sheet Josh fin.qxd 7/13/2015 8:38 PM Page 1

यूनिवर्सल एक्सेस टु फोन स्कीम के तहत देश के 42,300 ऐसे गांवों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जहां अब तक फोन सर्विस नहीं है।

में करीब एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना है। टेलीकॉम कंपनीज ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। फिलहाल 50 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, नागरिकों को डिजिटल लिटरेट बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (एनआइइएलआइटी) आइटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ई-लिटरेसी और कैपिसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चला रहा है, फॉर्मल और नॉन-फॉर्मल कोर्सेज कंडक्ट कर रहा है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग, जीआइएस, साइबर सिक्योरिटी, आइपीआर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई-गवर्नेंस जैसे कोर्सेज शामिल हैं। ई-गवर्नेंस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एनआइइएलआइटी लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही है। इसके तहत उन्हें कंप्यूटर चलाने, ई-मेल भेजने-रिसीव करने, इंटरनेट का उपयोग करने की बेसिक नॉलेज दी जाती है।

डिजिटल जॉब्स होंगे क्रिएट

डिजिटाइजेशन से नई नौकरियां क्रिएट होंगी, लेकिन इसके लिए पहले उन सेक्टर्स की पहचान करनी होगी, जहां डिजिटल जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हों। मसलन, लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने, बैक एंड फैसिलिटेटर के रूप में काम करने या वॉयस बेस्ड बीपीओ इंडस्ट्री में टेली कॉलिंग जैसे जॉब्स के लिए ट्रेंड मैनपॉवर की जरूरत होगी। इसके अलावा, नॉलेज बेस्ड वर्क जैसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पेटेंट कराने या फिर वर्चुअल असिस्टेंस सपोर्ट जैसे काम के लिए टेक्निकल मैनपॉवर चाहिए होगा।

अश्वंथ, बिजनेस हेड, देसी क्रू, चेन्नई

ई-गवर्नेंस लाएगा पारदर्शिता

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत देश को डिजिटिली एम्पॉवर्ड नॉलेज इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित करना है। टेक्नोलॉजी के जरिये गवर्नेंस में सुधार लाना है। इसलिए पंचायतों से लेकर बैंकों, अस्पतालों, सरकारी विभागों का सारा काम ऑनलाइन होगा। देश के करीब डेढ़ लाख पोस्ट ऑफिस को डिजिटल केंद्र के रूप में विकसित करने की भी योजना है। हर पोस्टमैन को एक मोबाइल फोन दिया जाएगा, ताकि पोस्टल सुविधाओं की कमियों को दूर किया जा सके। वहीं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को भी ब्रॉडबैंड से जोड़ने की बात है। ऐसा होने पर जमीन का रिकॉर्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, वोटर आइ कार्ड और दूसरी सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगी। लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस तरह विभिन्न सरकारी विभागों के कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी। ई-गवर्नेंस का यह भी फायदा होगा कि इससे अलग-अलग सरकारी विभागों में नई नौकरियां पैदा होंगी। मसलन, करीब 10 प्रमुख मंत्रालयों में चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रखे जाने हैं, जो ई-गवर्नेंस से संबंधित प्रोजेक्ट्स को डिजाइन, डेवलप और इम्प्लीमेंट करेंगे। *आइपीई ग्लोबल के* एजुकेशन ऐंड स्किल डेवलपमेंट के प्रैक्टिस हेड **अमित कौशिक** के अनुसार, डिजिटल इंडिया से उन स्टूडेंट्स को भी नौकरियों के अवसर मिलेंगे जो सिर्फ 10 वीं या 12वीं पास हैं। इन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग देकर मार्केट के लिए तैयार किया जा सकता है।

डिजिटल इंडिया के तहत पहल

- देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य। इसके लिए गांव के युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा।
- सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया पोर्टल, मोबाइल ऐप, माई गोव मोबाइल ऐप, स्वच्छ भारत मिशन ऐप और आधार मोबाइल अपडेट ऐप से भी युवाओं को रोजगार पाने में मदद मिलेगी।
- दूरसंचार मंत्रालय द्वारा 11 राज्यों में शुरू किए जा रहे 'भारत नेट' के तहत देश में वाई-फाई सुविधा की शुरुआत की जाएगी।
- ई-बस्ता पोर्टल के जरिए एनसीईआरटी की किताबों को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि गांव के बच्चे इन किताबों को अपने स्मार्टफोन पर पढ़ सकें।
- डिजिटल लॉकर सिस्टम की शुरुआत से अपने सर्टिफिकेट्स को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होगी।
- ई-हॉस्पिटल सर्विस के माध्यम से सुदूर गांव में रह रहा आम आदमी भी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये सीधे एम्स और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी हॉस्पिटल्स से जुड़कर सलाह और दवाओं की सुविधा हासिल कर सकेगा।

ई-हॉस्पिटल से नई क्रांति

जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे कुछ प्रमुख अस्पतालों में मरीजों की भीड़ साल-दर-साल बढ़ रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर-पूर्व और दूर-दराज के अन्य गांवों के हजारों लोग बेहतर इलाज के

10-11 cover1_style sheet Josh fin.qxd 7/13/2015 8:39 PM Page 2

देश की सभी यूनिवर्सिटीज को वाई-फाई से जोड़ा जायेगा और 2.5 लाख स्कूलों में भी वाई-फाई होगा। 2019 तक 4 लाख पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्वाइंट बनेंगे।

लिए एम्स पहुंचते हैं, लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद कहीं जाकर उनका नंबर लग पाता है। अब इस समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जिसके माध्यम से दूसरे प्रदेशों और गांवों के लोग घर बैठे दिल्ली के एम्स, राम मनोहर लोहिया और बेंगलुरु के निमहांस अस्पताल में इलाज के लिए अप्वाइंटमेंट ले सकेंगे। इनके अलावा, देश भर के 30 अन्य बड़े अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दरअसल, ई-हॉस्पिटल एक ऐसी क्लाउड बेस्ड सर्विस है, जिसके जरिये देशभर के सभी सरकारी अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम (ओआरएस) फ्रेमवर्क के तहत कोई भी शख्स हॉस्पिटल में अप्वाइंटमेंट, लैब रिपोर्ट और ब्लड अवलेबिलिटी चेक कर सकेगा। अगर किसी को डोनर की जरूरत होगी, तो उसका अप्वाइंटमेंट भी ऑनलाइन मिल सकेगा। पूरी प्रक्रिया आधार कार्ड पर आधारित होगी, यानी आधार कार्ड होने पर आप ई-हॉस्पिटल के पोर्टल पर रजिस्टर कर सकेंगे। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा तैयार किया गया ई-हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ काम करता है।

व्हाट्सअप से होगा बिजनेस

इंडिया में आज 10 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन हैं, जो दिनों-दिन बढ़ रहे हैं। इससे ई-कॉमर्स स्पेस भी बदल रहा है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जोमैटो, ओला जैसी तमाम कंपनीज वेबसाइट प्लेटफॉर्म से ऐप पर शिफ्ट हो रही हैं। अब खासकर व्हाट्सअप पर नए बिजनेस मॉड्यूल्स तैयार किए जा रहे हैं। नए एंटरप्रेन्योर्स ऐप और चैट ओरिएंटेड इंटरफेस को प्रिफरेंस दे रहे हैं। इस डिजिटाइजेशन से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। गांव में बैठा एक व्यापारी ऑनलाइन माध्यम से अपना प्रोडक्ट बड़े बाजार तक पहुंचा सकेगा।

चंदन गुप्ता, सीइओ, फोन वॉरियर

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज

इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को देखें, तो साल 2014 तक इंटरनेट के इस्तेमाल में इंडिया, अमेरिका और चीन से पीछे था। लेकिन साल 2020 तक देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। लोग मोबाइल फोन के जरिये ही इंटरनेट एक्सेस करेंगे। शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की तादाद 50 प्रतिशत तक बढ़ेगी। हालांकि एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में इंडिया की औसत इंटरनेट स्पीड अब भी बेहद धीमी है, सरकार कंपनियों पर इसे बढ़ाने का दबाव बढ़ा रही है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क *एकामई (एकेएएमएआइ) टेक्नोलॉजीज की क्वार्टरली स्टेट ऑफ द इंटरनेट रिपोर्ट 2014* के अनुसार, भारत में इंटरनेट की औसत स्पीड 2 एमबीपीएस है, जबकि दक्षिण कोरिया में 25.3 एमबीपीएस। डिजिटल इंडिया की सफलता की राह में यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ने मार्च 2017 तक देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। *दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज* के डायरेक्टर **आश नारायन रॉय** की मानें, तो देश का विकास हो रहा है, लेकिन ग्रोथ जॉबलेस है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो लाखों नौकरियों के सपने दिखाए गए हैं, उनको हकीकत में बदलने के लिए योजना का सटीक मूल्यांकन जरूरी है। डिजिटल इंडिया सिर्फ स्लोगन भर बनकर न रह जाये, इसके लिए ग्राउंड मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसी तरह ई-पंचायत को सफल बनाने के लिए गांवों में बिजली की समस्या दूर करना जरूरी है।

कॉन्सेप्ट ऐंड इनपुट : **अंशु सिंह, आरती सिंह**

ई-हॉस्पिटल से होगा सशक्तीकरण

सरकारी अस्पतालों को ऑनलाइन करने के लिए सही प्रयास और मोटिवेशन की जरूरत है, तभी स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक बदलाव आएगा। सभी सरकारी अस्पतालों को ऑनलाइन करने से आम आदमी का सशक्तीकरण होगा और वे सुविधाओं का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। ई-हॉस्पिटल का सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि इससे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। सरकारी अस्पतालों में ग्राउंड स्टाफ की मिलीभगत से मरीज दिखाने में जो धांधलेबाजी होती है, उस पर रोक लगेगी। रोजगार के लिहाज से देखें, तो अकेले एम्स के ऑनलाइन सिस्टम को चलाने के लिए 100 से ज्यादा लोगों की टीम है, जिनमें 70 नर्स, 15 प्रोग्रामर कॉल सेंटर में 10 लोग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर में काम करने वाले लोग शामिल हैं। डिजिटल इंडिया के तहत हर सरकारी अस्पताल को ऑनलाइन करने के लिए कम से कम 8-10 नए स्टाफ की जरूरत होगी।

डॉ. दीपक अग्रवाल, चेयरमैन कंप्यूटराइजेशन, एम्स, नई दिल्ली